मानानीया श्री राज्यपाल, उ0प्र0 की अध्यक्षता में निधि की प्रबन्ध समिति की 47वीं बैठक दिनांक 28 जुलाई 2020

KEEP YOUR DISTANCE

पूर्व सैनिकों की पुत्रियों के लिए विवाह अनुदान दोगुना

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

लखनऊ।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में हुई सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंध समिति की बैठक में पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ संचालित वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि को बढ़ाकर डेढ़ से दोगुना करने का निर्णय लिया गया। वहीं पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह अनुदान योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया गया।

राज्यपाल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंध समिति की 47वीं बैठक

राज्यपाल श्रीमती पटेल की अध्यक्षता में यहां राजभवन में उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंध समिति की मंगलवार को 47वीं बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के पूर्व सैनिकों के 9-10 के छात्रों को दी जाने वाली धनराशि 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रूपये, 11-12 के छात्रों के लिए 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये, स्नातक स्तर के छात्रों के लिए 5,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये, स्नातकोत्तर स्तर के लिए 6,000 बढ़ाकर 9,000 रूपये करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा इन्टर स्तर तक के तकनीकी कोर्स (आईटीआई आदि) के लिए 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रूपये तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी कोर्स के लिए 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रूपये कर दिया गया है। शहीद सैनिकों के आश्रितों को तकनीकी ट्रेनिंग प्राप्त करने तथा इससे संबंधित उपकरण खरीदने के लिए 50,000 रूपये तक की आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्णय लिया गया। राज्यपाल ने सैनिक पुनर्वास निधि के सचिव ब्रिगेडियर रवि को निर्देश दिया कि जो भी वजट शहीद सैनिकों के आश्रितों के सहायतार्थ स्वीकृत किए गये है, पूरी धनराशि का अधिकतम उपयोग करें। इससे पहले निदेशक उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण एवं निधि के सचिव ब्रिगेडियर रवि ने प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की और आयव्यय का लेखा-जोखा भी रखा। वीडियो कफ्रिन्सिंग के दौरान राज्यपाल ने सचिव राजस्व को अगस्त तक अटारी कृषि प्रक्षेत्र की 1342 एकड़ भूमि के चिन्हीकरण एवं सीमांकन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी को निर्देश दिया कि वे इस कृषि फार्म का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण करें तथा इसकी रिपोर्ट राजभवन को दें कि इस कृषि प्रक्षेत्र का वेहतर उपयोग कैसे किया जाय और इसकी आय में किस प्रकार वृद्धि की जाय, क्योंकि वर्तमान में इस प्रक्षेत्र से कुल 9.69 लाख रूपये की शुद्ध आय हुई है जो कृषि क्षेत्र के हिसाब से उचित नहीं है। उन्होंने कृषि प्रक्षेत्र पर लगे 8 नलकूपों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए संबंधित विभाग से प्रस्ताव तैयार कराकर उसे शीघ्र चालू करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव राज्यपाल महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, सचिव राजस्व संजय कुमार के अलावा प्रवन्ध समिति के अन्य सदस्य भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे।

पूर्व सैनिकों की विधवाओं को पुत्रियों के विवाह के लिए अब मिलेंगे एक लाख रुपये

हाईस्कूल से स्नातकोत्तर तक के छात्रों की शैक्षिक सहायता की राशि भी बढ़ाई गई

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में मंगलवार राजभवन में उप्र सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंध समिति की 47वीं बैठक हुई। इसमें पूर्व सैनिकों की विधवाओं को पुत्रियों के विवाह अनुदान योजना के तहत दी जाने वाली 50 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा बैठक में प्रदेश के पूर्व सैनिकों के कल्याण के उद्देश्य से संचालित वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना के तहत हाईस्कूल के छात्रों को आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाने वाली 3 हजार की राशि को बढ़ाकर 5 हजार, इंटर के छात्रों को दी जाने वाली 4 हजार रुपये की राशि को 6 हजार करने, स्नातक छात्रों की राशि 5 हजार से 7 हजार करने और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों

की राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार करने का निर्णय लिया गया।

इसी तरह इंटर स्तर तक के तकनीकी कोर्स (आईटीआई आदि) को दी जाने वाली 7 हजार की राशि को बढ़ाकर 10 हजार व स्नातक एवं स्नातकोतर स्तरीय तकनीकी कोर्स के छात्रों को दी जाने वाली 15 हजार की राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही शहीद सैनिकों के आश्रितों को तकनीकी ट्रेनिंग प्राप्त करने और इससे संबंधित उपकरण खरीदने के लिए भी 50 हजार की आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्णय लिया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक के दौरान राज्यपाल ने सचिव राजस्व को अगस्त तक अटारी कृषि प्रक्षेत्र की 1342 एकड़ भूमि के चिह्नित एवं सीमांकन कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी को निर्देश दिए कि वे इस कृषि फार्म का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण करें तथा इसकी रिपोर्ट राजभवन को दें कि इस कृषि प्रक्षेत्र का बेहतर उपयोग कैसे किया जाय और इसकी आय में किस प्रकार वृद्धि की जाय।

राज्यपाल ने सैनिक पुनर्वास निधि के सचिव ब्रिगेडियर रवि को निर्देश दिए कि जो भी बजट शहीद सैनिकों के आश्रितों के सहायतार्थ स्वीकृत किए गये हैं, पूरी राशि का अधिकतम उपयोग करें। इससे पहले निदेशक उतर प्रदेश सैनिक कल्याण एवं निधि के सचिव ब्रिगेडियर रवि ने प्रबंध समिति की 46वीं बैठक की कार्यवृत की पुष्टि हेतु राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की और आय-व्यय का लेखा-जोखा भी रखा।

सुनवाई होगी। बिजली कंपनियों को ... दिन में अखबारों में प्रकाशित करना होगा। तक बिजली कंपनियों ने कोई बढ़ोतरी

पूर्व सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए और मिलेगा पैसा

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यूपी सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंध समिति की बैठक में कई मदों में सहायता बढ़ाने का फैसला लिया गया। बैठक में पूर्व सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता राशि बढ़ाने के साथ सैनिकों की विधवाओं की बेटियों के विवाह अनुदान की राशि को 50 हजार की जगह एक लाख रुपये कर दी गई।

सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंध समिति की बैठक में धनराशि बढ़ाने की मंजूरी

पूर्व सैनिकों के बच्चों की वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना के तहत अब कक्षा नौ और 10 के स्टूडेंट्स को तीन हजार की जगह पांच हजार और 11-12 के छात्रों को चार हजार की जगह छह हजार रुपये मिलेंगे। स्नातक के लिए पांच हजार की जगह सात हजार, स्नातकोत्तर स्तर के लिए छह हजार की जगह नौ हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे। इंटर स्तर तक के तकनीकी कोर्स (आईटीआई आदि) के लिए सात हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये, स्नातक-स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी कोर्स के लिए 15,000 की जगह 25,000 रुपये मिलेंगे।

तकनीकी ट्रेनिंग के लिए मिलेगा 50 हजार रुपये : शहीदों के आश्रितों को तकनीकी ट्रेनिंग और इससे संबंधित उपकरण खरीदने के लिए 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्यपाल ने सचिव (राजस्व) को अगस्त तक अटारी कृषि प्रक्षेत्र की 1,342 एकड़ भूमि के चिह्नीकरण और सीमांकन के निर्देश दिए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव (कृषि) देवेश चतुर्वेदी को निर्देश दिए कि वे इस कृषि फार्म का निरीक्षण कर राजभवन को रिपोर्ट दें कि प्रक्षेत्र का बेहतर उपयोग कर आय में कैसे इजाफा किया जाए। इस दौरान सैनिक पुनर्वास निधि के सचिव ब्रिगेडियर रवि भी मौजूद रहे।